

उपायुक्त -सह- जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला।
(विधि शाखा)

म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)वाद सं० :-117/2023-24

महावीर साहु वगै०

बनाम

गौरी देवी वगै०

06.7.24

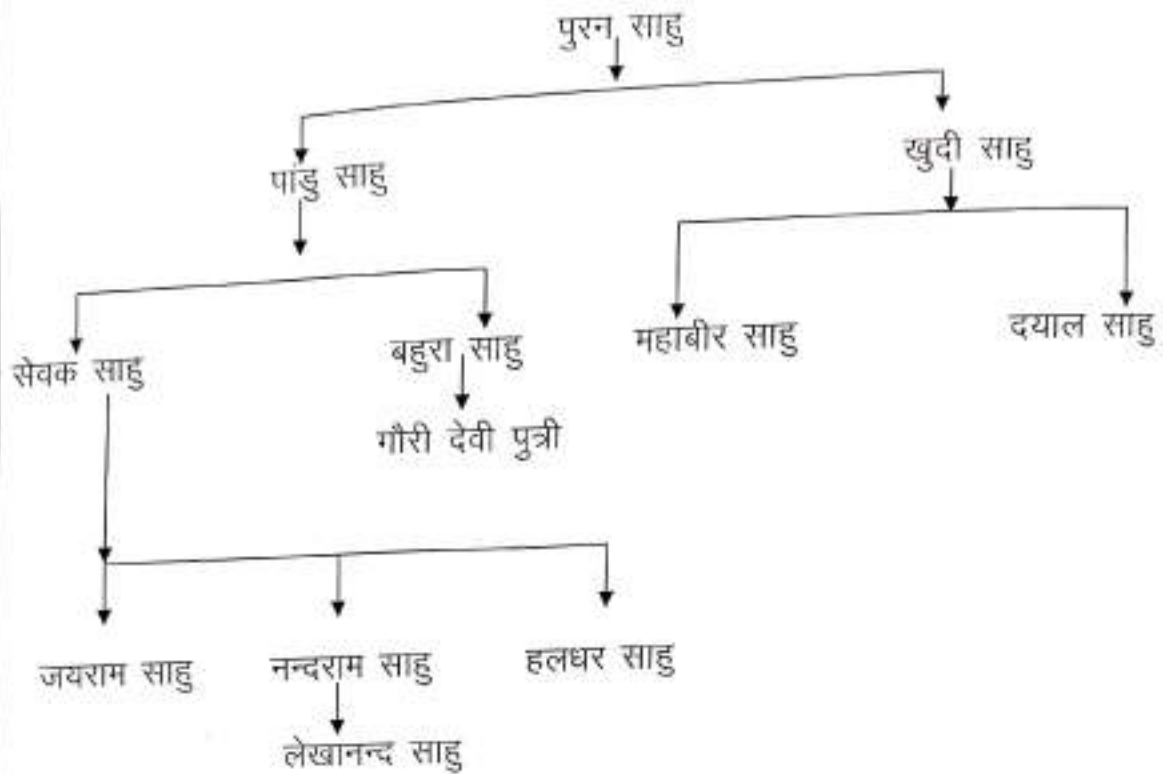
1. अपीलार्थी महावीर साहु 2. दयाल साहु दोनों के पिता-स्व० खुदी तेली ग्राम-लावागाई नवाटोली पो०-भुरसो थाना-सिसई जिला-गुमला के द्वारा उप समाहर्ता भूमि सुधार गुमला के दाखिल-खारिज अपील वाद सं०-19/2018-19 में दिनांक-15.09.2023 को पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थीगण के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया।

2. अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में जानबुझकर न्यायालय से धोखा धड़ी करने के उद्देश्य से हस्तक्षेपी महावीर साहु व दयाल साहु को पक्षकार नहीं बनाते हुए अपील वाद सं०-19/2018-19 दायर किया गया था जबकि प्रश्नगत भूमि मौजा-लावागाई थाना-सिसई जिला-गुमला के अवस्थित खाता सं०-29 प्लॉट सं०-424 रकबा-0.96 एकड़ एवं प्लॉट सं०-737 रकबा-0.81 एकड़ कुल रकबा-1.77 एकड़ भूमि का जमाबंदी अपीलार्थी के नाम से कायम है। बाद में इस अपील वाद की जानकारी के पश्चात अपीलार्थी मध्यक्षेपी आवेदन दाखिल कर निम्न अपीलीय न्यायालय में पक्षकार बने हैं।

3. अपीलार्थी के पिता स्व० खुदी साहु मौजा-लावागाई नवाटोली पो०-भुरसो अंचल सिसई जिला-गुमला के निवासी थे। प्रश्नगत भूमि के खरीदगी के अनुरूप खाता सं०-29 प्लॉट सं०-424 रकबा-0.96 एकड़ एवं प्लॉट सं०-737 रकबा-0.81 एकड़ कुल रकबा-1.77 एकड़ भूमि का उनके नाम पर पंजी ii में जमाबंदी दर्ज है, जिसका लगान रसीद निर्गत हो रहा है। अपीलार्थी के पिता स्व० खुदी साहु के नाम पर जमाबंदी में दर्ज प्लॉट सं०-736/834 रकबा-1.51 एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कराकर महावीर साहु व दयाल साहु के नाम पर रसीद निर्गत हो रहा है।

4. प्रश्नगत खाता सं०-29 प्लॉट सं०-424/737 रकबा-3.54 एकड़ भूमि का पूर्व में सादा हुकुमनामा से स्व० पाण्डे साहु एवं खुदी साहु के द्वारा संयुक्त रूप से भूमि कय किया गया था। हिस्से को लेकर पूरब तरफ की भूमि का सीमांकन स्व० खुदी साहु के पुत्र महावीर साहु व दयाल साहु द्वारा कराया जाना लगा तभी आपसी बंटवारा को लेकर उनके मध्य विवाद हो गया। प्रश्नगत भूमि का सीमांकन के विरुद्ध आपत्ति दायर किया गया। महावीर साहु व दयाल साहु के नाम पर किया गया उत्तराधिकारी नांमांतरण वाद सं०-99 आर 27/2009-10 के विरुद्ध महावीर साहु के सीमावर्ती पड़ोसी गौरी देवी पति विन्ता साहु ग्राम-छारदा अंचल सिसई जिला-गुमला द्वारा नांमांतरण अपील वाद सं०-19/2018-19 भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला के न्यायालय में दायर किया गया है। उभय पक्षों का वशावली निम्नलिखित रूप से है:-



5. गौरी देवी बंटवारा वाद सं०-७७/१९७६ में पारित फाईनल डिक्री दिनांक-३०.०३.८९ के आलोक में प्रश्नगत भूमि में नाजायज दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्नगत बंटवारा वाद के दरमियान अपीलार्थी महाबीर साहु वो दयाल साहु के पिता खुदी साहु का हेहान्त दिनांक-१३.०७.१९८१ को हो गया परन्तु गौरी देवी न्यायालय के साथ धोखा-धड़ी करते हुए मृत व्यक्ति खुदी साहु के नाम फाईनल डिक्री दिनांक-३०.०३.८९ को ले लिया तथा महाबीर साहु वो खुदी साहु को पक्षकार जानबुझकर नहीं बनाया। कालान्तर में बंटवारा वाद सं०-७७/७६ के फाईनल डिक्री के छेड़-छाड़ करते हुए दिनांक-१५.०५.८९ को वगैर समक्ष न्यायालय के आदेश के खुदी साहु का नाम फाईनल डिक्री से हटा दिया। विधि का सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के खिलाफ प्राप्त डिक्री प्रभावहीन है।

6. गौरी देवी पुनः न्यायालय के साथ धोखा धड़ी करते हुए वगैर महाबीर साहु वो दयाल साहु को पक्षकार बनाते हुए इजराय वाद सं०-०४/१९८९ में न्यायालय से कागजी तौर पर दखलदेहानी आदेश प्राप्त कर लिया, परन्तु महाबीर साहु वो दयाल साहु को बंटवारा वाद सं०-७७/७६ एवं इजराय वाद सं०-०४/८९ में पक्षकार नहीं बनाया गया था। प्रश्नगत बंटवारा वाद सं०-७७/७६ एवं इजराय वाद सं०-०४/८९ में प्राप्त दखल देहानी का आदेश महाबीर साहु वो दयाल साहु के विरुद्ध प्रभावकारी नहीं हो सका और प्रश्नगत भूमि खाता सं०-२९ प्लॉट सं०-४२४ रकबा-०.९६ एकड़ एवं प्लॉट सं०-७३७ रकबा-०.८१ एकड़ कुल रकबा-१.७७ एकड़ वो प्लॉट सं०-४२४/८३४ रकबा-१.५१ एकड़ का जमाबन्दी खुदी साहु के नाम कायम था। कालान्तर में उपरोक्त वर्णित भूमि का उत्तराधिकारी के तौर पर हासिल कर अपीलार्थी महाबीर साहु वो दयाल साहु हक दखलकार है तथा उनके नाम उत्तराधिकारी दाखिल खारिज वाद सं०-९९ आर २७/२००९-१० से दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है।

7. प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा गुमला द्वारा प्रेषित जॉच प्रतिवेदन ज्ञापांक-५७३४/ii गो० दिनांक-२८.१०.२०२२ से स्पष्ट होता है कि महाबीर साहु वो दयाल साहु के हित में पंजी ii में नाम संधारित होने तथा रसीद निर्गत होने की

पुष्टि होती है। महावीर साहु वो दयाल साहु बंटवारा वाद सं०-७७/७६ में पक्षकार नहीं थे, तथा वह आदेश मृत व्यक्ति खुदी साहु के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था। मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित आदेश/डिकी शून्य होता है। इजराय वाद सं०-०४/८९ में पारित आदेश कभी अमल प्रभाव में नहीं आ सका। गौरी देवी बंटवारा वाद सं०-७७/७६ में पारित डिकी मुताबिक विगत ३० वर्ष से अधिक समय तक दाखिल खारिज नहीं करा सकी, तथा यह भी विधि का सिद्धान्त है कि भारतीय परिसीमन अधिनियम में वर्णित प्रावधानधारा के अनुरूप यदि डिकी पारित हुए १२ वर्ष से अधिक समय हो गया है। अपीलार्थी का दखल प्रश्नगत भूमि प्लॉट सं०-४२४, ७३७ एवं प्लॉट सं०-४१४/७३४ में पृष्टि है एवं जमाबन्दी कायम है। निम्न अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत नहीं है।

अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी सं०-०१ का पक्ष

८. उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं०-१९/२०१८-१९ में पारित आदेश दिनांक-१५.०९.२०२३ के विरुद्ध दायर किया गया है उक्त अपील में वर्तमान उत्तरवादी सं०-०१ गौरी देवी की अपील को विधि सम्मत तरीके से निम्न न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। रिबीजन वाद में खाता सं०-३४, ३८, ११२, १११, ८८, ७५, २९, २८, २, ७५ एवं ४० की भूमि जो ग्राम लावागाई थाना-सिसई जिला-गुमला एवं खाता सं०-३३ व ३४ की भूमि जो ग्राम-सियांग थाना-सिसई जिला-गुमला में अवस्थित है। प्रश्नगत भूमि पक्षकारों की संयुक्त सम्पत्ति थी तथा इनके अलावे भी उपरोक्त खाता की भूमि पुश्तैनी सम्पत्ति थी जिसके बंटवारा हेतु उत्तरवादी गौरी देवी व उसकी माता मोसमात सीता साहु द्वारा बंटवारा वाद सं०-७७/७६ एवं ०४/७९ सब जज गुमला के न्यायालय में दायर किया था जो दिनांक-२६.०९.१९७९ के निर्णय व डिकी द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त निर्णय व डिकी के विरुद्ध अन्य हिस्सेदार सेवक साहु वगैरह जो अपीलार्थी के पूर्वज थे के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय रॉची बेंच में प्रथम अपील वाद सं०-३१९/१९७९ दायर किया गया जिससे निम्न न्यायालय के निर्णय व डिकी को यथावत रखते हुए अपील को दिनांक-२१.१२.१९८७ के निर्णय व डिकी को निरस्त कर दिया।

९. उक्त दोनों निर्णय व डिकी के आधार पर बंटवारा वाद सं०-७७/७६ एवं ०४/७९ में फाईनल डिकी दिनांक-३०.०३.१९८९ को पारित करते हुए गौरी देवी व मसोमात सीता साहुन के हिस्से को अलग कर दिया गया उसी हिस्से के नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा या रिबीजन दायर किया गया है। उत्तरवादी सं०-०१ गौरी देवी व उसकी माता द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर दखल प्राप्त करने हेतु इजराय वाद सं०-०४/१९८९ सब जज-१ गुमला के न्यायालय में दायर किया जिसमें दिनांक-२३.१०.१९९१ को न्यायालय की प्रक्रिया से गौरी देवी को दखल दिहानी दिलाई गई उस समय सीता साहुन की मृत्यु हो चुकी थी। न्यायालय द्वारा दखल दिहानी दिलाए जाने के पश्चात उत्तरवादी सं०-०१ गौरी देवी अपने हिस्से की भूमि पर शान्ति पूर्वक दखलकार चली आ रही है।

१० अपीलार्थीगण द्वारा बंटवारा की अपील निरस्त होने के पश्चात फुलो देवी नामक महिला से बंटवारा वाद सं०-७७/७६ एवं ०७/७९ में पारित निर्णय व डिकी को निरस्त कराने हेतु एक टाईटल सुट न०-२८/१९८८ दायर कराया गया

व वाद दिनांक-30.03.1993 के निर्णय व डिकी द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय व डिकी के विरुद्ध फूलों देवी द्वारा अपर जिला न्यायाधीश-I गुमला के न्यायालय में अपील की दायर किया गया जिसका टाइटल अपील सं0-31/1993 था, उक्त अपील को दिनांक-19.09.2000 के निर्णय व डिकी द्वारा खारिज कर दिया गया। अपीलार्थीगण व उनके पूर्वजों का बंटवारा वाद के निर्णय व डिकी को निरस्त करने का हर प्रयास विफल होने के बावजूद बिना किसी हक सरोकर के उत्तरवादी सं0-01 गौरी देवी को परेशान किया जा रहा है।

11 उत्तरवादी सं0-01 गौरी देवी के द्वारा सक्षम न्यायालय के निर्णय से मिले अपने हिस्से की भूमि के नामान्तरण हेतु अंचल अधिकारी सिसई के न्यायालय में आवेदन दिया जिसका नामान्तरण वाद सं0-34 आर 27/2018-19 था, परन्तु उपरोक्त सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए दिनांक-16.08.2018 को नामान्तरण वाद को खारिज कर दिया गया। उत्तरवादी सं0-01 गौरी देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया गया, जिसमें सभी विधि व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक-15.09.2023 के आदेश द्वारा नामान्तरण अपील वाद सं0-19/2018-19 को स्वीकृत कर अंचल अधिकारी सिसई को उत्तरवादी गौरी देवी के पक्ष में बंटवारा वाद के निर्णय व डिकी के आलोक में नामान्तरण स्वीकृत करने का आदेश दिया गया।

12 अपीलार्थीगण का यह कथन कि सक्षम न्यायालय की निर्णय व डिकी मरे हुए व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है इसलिए उक्त निर्णय व डिकी उनपर बाध्यकारी नहीं है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों द्वारा उक्त बंटवारा वाद व उसका अपील दायर कर अपने सारे विधि के विकल्प को उपयोग किया जा चुका था तथा फूलों देवी से बंटवारा वाद के निर्णय व डिकी को चुनौती दिलवाई गई उसके बावजूद भी आदेश बरकरार रहा और उत्तरवादी गौरी देवी को न्यायालय की प्रक्रिया से दखल दिहानी दिलाई गई एवं 30 वर्षों के बाद नया तथ्य अपीलार्थीगण द्वारा लाया जाना उसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है, इसलिए उनका यह आधार निराधार है। फूलों देवी के वाद में सभी अपीलार्थीगण पक्षकार थे व सभी तथ्यों की जानकारी उन्हें प्रारम्भ से ही था।

13. अपीलार्थीगण का यह कथन कि अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन में कुल 5 प्लॉटों पर अपीलार्थीगण का दखल दिखाया गया है। उक्त 5 प्लॉट का नामान्तरण उत्तरवादी गौरी देवी के नाम पर नहीं किया जाना चाहिए। उत्तरवादी का प्रश्नगत भूमि पर न्यायालय की प्रक्रिया से दखल दिहानी दिलाई गई है और अंचल अमीन के प्रतिवेदन में भी लगभग 99 प्रतिशत भूमि पर गौरी देवी का दखल अंकित किया गया है। सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिकी तथा दखल दिहानी के विपरीत जाकर आदेश राजस्व न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय झारखण्ड न्यायालय का न्यायादेश जो JLJR 2012(3) पेज सं0-25 में रिपोर्टेड है। भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला द्वारा पारित आदेश पूर्णतः न्यायोचित है तथा आदेश माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेशों को दृष्टिगत रखते हुए पारित किया गया है।

उत्तरवादी सं0-01 गौरी देवी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपील वाद को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. J.L.J.R-2012(3) पेज सं०-25 की छाया प्रति।
2. T.S NO.-28/1988 में पारित आदेश एवं डिक्री का सच्चीप्रतिलिपि का छाया प्रति।
3. T.A NO.-31/93 में पारित आदेश एवं डिक्री का सच्चीप्रतिलिपि का छाया प्रति।
4. P.S NO.-77/76 एवं 4/79 का फाईलन डिक्री एवं दखन देहानी प्रतिवेदन का सच्चीप्रतिलिपि की छाया प्रति।
5. G.R Case No.-716/23 का F.I.R का सच्चीप्रतिलिपि का छाया प्रति।

उत्तरवादी सं०-02,03, एवं 04 का पक्ष

14 उत्तरवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला द्वारा दाखिल खारिज अपील सं०-19/2018-19 में दिनांक-15.09.2023 को पारित आदेश विधि सम्मत नहीं, जो खारिज करने योग्य है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की वैधानिकता को दरकिनार करके पारित किया गया है, जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश म्यूटेशन एक्ट के विरुद्ध है। प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज होने के लिए आवेदक का भूमि पर लगख होना आवश्यक है। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी गौरी देवी का दखल कभी नहीं रहा है।

15 उत्तरवादीगण गौरी देवी के द्वारा पार्टिसन सूट सं०-77/76 एवं इजराय वाद सं०-04/89 के आदेश को आधार मानकर प्रश्नगत भूमि का दाखिल खारिज कराने हेतु आवेदन दिया गया है वह आदेश विधि सम्मत नहीं है। प्रश्नगत भूमि का दखल देहानी भूमि पर जाकर वैधानिक रूप से नहीं किया गया है। मौजा-लावागाई थाना-सिसई जिला-गुमला का प्रश्नगत भूमि का खाता सं०-29 प्लॉट सं०-424 रकबा-0.96 एकड़ वो प्लॉट सं०-737 रकबा-0.81 एकड़ वो प्लॉट सं०-736/834 रकबा-1.51 एकड़ भूमि खुदी साहु का निजी भूमि है एवं खुदी साहु की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जमाबंदी महाबीर साहु वो दयाल साहु के नाम से कायम है। प्रश्नगत भूमि पर शान्तिपूर्ण दखलकार रहकर हर वर्ष सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे हैं।

16 उत्तरवादी गौरी देवी के द्वारा मौजा-लावागाई थाना सिसई जिला गुमला के खाता सं०-88 प्लॉट सं०-478 रकबा-0.86 एकड़ भूमि के दाखिल खारिज हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दिया गया है। प्रश्नगत प्लॉट सं०-478 खाता सं०-88 का भूमि नहीं है। प्रश्नगत प्लॉट सं०-478 मौजा-लावागाई थाना-सिसई जिला-गुमला के खाता सं०-2 की भूमि है, जिसका जमाबंदी सोमा पुजार के नाम से कायम है तथा सोमा पुजार के वारिसान प्रश्नगत भूमि में शान्तिपूर्वक दखलकार रहकर हर वर्ष सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहे हैं।

17 उत्तरवादी गौरी देवी ग्राम-छारदा थाना-सिसई जिला-गुमला की निवासी है तथा प्रश्नगत भूमि ग्राम छारदा से करीब 10 कि० मी० दूर ग्राम लावागाई में है। प्रश्नगत भूमि में गौरी देवी के दखलकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तथा गौरी देवी भूमि पर दखलकार नहीं है तो भूमि का दाखिल खारिज कानूनन रूप से गौरी देवी के नाम से नहीं हो सकता है। भूमि का दाखिल खारिज के लिए संबंधित भूमि के वैध कागजात के साथ-साथ दावेदार का दखल होना आवश्यक है। भूमि का वैध कागजात होते हुए भी भूमि में दावेदार का दखल नहीं है तो दावेदार के नाम से दाखिल खारिज नहीं हो सकता है।

18. उत्तरवादी गौरी देवी के द्वारा इजराय वाद के आदेश के 25 वर्ष बाद दाखिल

खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है। कानूनन गौरी देवी को आदेश की तिथि के बाद 12 वर्ष के अन्दर ही दाखिल खारिज कराना था, परन्तु उत्तरवादी के द्वारा दाखिल खारिज का आवेदन आदेश के 25 वर्ष के बाद आवेदन समर्पित किया गया है। कानूनन गौरी देवी के नाम से दाखिल खारिज हो ही नहीं सकता है। उत्तरवादी गौरी देवी के द्वारा इजराय वाद सं०-04/89 के आदेश के 25 वर्ष बाद दाखिल खारिज हेतु आवेदन समर्पित किया गया है। सोमा पुजार के खाता की भूमि को आवेदन में शामिल करने तथा प्रश्नगत भूमि में गौरी देवी का दखल नहीं होने एवं खुदी साहु की निजी भूमि को आवेदन में शामिल करने के कारण अंचल अधिकारी सिसई के द्वारा गौरी देवी का दाखिल खारिज आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, जो विधि सम्मत है।

19 भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं०-19/2018-19 में दिनांक-15.09.2023 में पारित आदेश के द्वारा अंचल अधिकारी सिसई के दाखिल खारिज वाद सं०-27 आर 27/2018-19 में निर्णित आदेश को खारिज करना न्याय हित में उचित नहीं है।

उत्तरवादी सं०-02,03, एवं 04 के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता गुमला द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील वाद स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादीगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन निम्नांकित कागजातों की छाया प्रति संलग्न किया गया है।

1. J.B.C.J 2014 (3) पेज सं०-188 की छाया प्रति।
2. P.L.J.R (3) पेज सं०-245 की छाया प्रति।
3. C.W.J.R. N0-2657/2000 R की छाया प्रति।

उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों व निम्न न्यायालय के आदेश के सम्यक अवलोकन व समीक्षा से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार, उप-समाहर्ता, गुमला द्वारा अपीलार्थीगण के दावा के संदर्भ में वैधिक दखल कब्जा की स्थिति पर विचार किये बिना ही आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में भूमि सुधार उप-समाहर्ता गुमला द्वारा Mutation Appeal Case No. - 19/2018-19 में पारित आदेश को निरस्त करते हुए वैधिक दखल-कब्जा की स्थिति का जांचोपरान्त सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए The Bihar Tenants Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 का अनुपालन कर तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु वाद Remand किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न अपीलीय न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ भेजे।

लेखापित्र एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला